



लेखापरीक्षा दिवस-2021
AUDIT DIWAS-2021



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

लोक लेखापरीक्षा और लेखांकन
में अभिनवता और उत्कृष्टता
के लिए सीएजी पुरस्कार

CAG's Awards for
Innovation and Excellence in
Public Auditing and Accounting

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
Indian Audit and Accounts Department



लेखापरीक्षा दिवस-2021
AUDIT DIWAS-2021

लोक लेखापरीक्षा और लेखांकन में अभिनवता
और उत्कृष्टता के लिए सीएजी पुरस्कार

CAG's Awards for Innovation and Excellence in
Public Auditing and Accounting

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
Indian Audit and Accounts Department

विषय-सूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
	लोक लेखापरीक्षा और लेखा में अभिनवता और उत्कृष्टता के लिए सीएजी पुरस्कार, 2021 के बारे में	4
1.	उत्पाद शुल्क अपवंचन को जाँचने के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा में प्रति-सत्यापन	6
2.	राज्य वित्त लेखापरीक्षा रिपोर्ट में ऋण स्थिरता विश्लेषण	8
3.	इंटरएक्टिव डिजिटल लेखापरीक्षा रिपोर्ट	10
4.	पेंशन संशोधन मामलों के आईटी सक्षम निपटान	12
5.	अस्पताल प्रबंधन की निष्पादन लेखापरीक्षा	14
6.	स्टॉर्म वाटर के प्रबंधन की निष्पादन लेखापरीक्षा	16
7.	उच्च शिक्षा में परिणाम आधारित लेखापरीक्षा की योजना और संचालन	18
8.	सिस्टम ऑटोमेशन इनिशियेटिव ट्रेनिंग एप्लिकेशन	20



Contents

Sl. No.	Subject	Page No.
	About CAG's Awards for Innovation and Excellence in Public Auditing and Accounting, 2021	5
1.	Cross verification in Compliance Audit to check evasion of excise duty	7
2.	Debt Sustainability Analysis in State Finances Audit Report	9
3.	Interactive Digital Audit Report	11
4.	IT enabled settlement of pension revision cases	13
5.	Performance Audit of Hospital Management	15
6.	Performance Audit of Management of Storm Water	17
7.	Planning and Conduct of Outcome Based Audit in Higher Education	19
8.	System Automation Initiative Training Application	21



लोक लेखापरीक्षा और लेखांकन में अभिनवता और उत्कृष्टता के लिए सीएजी पुरस्कार, 2021 के बारे में

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने लोक लेखापरीक्षा, लेखांकन, हकदारी और सहयोगी कार्यों के क्षेत्रों में भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किए गए असाधारण और अभिनव कार्यों को पहचानने और पुरस्कृत करने के लिए 'लोक लेखापरीक्षा और लेखा में अभिनवता और उत्कृष्टता के लिए सीएजी पुरस्कार' योजना की स्थापना की है। ये पुरस्कार कार्यात्मक क्षेत्रों, कार्य वातावरण और कल्याण के क्षेत्र में किए गए असाधारण प्रदर्शन और पहलों द्वारा समर्थित अभिनवता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना चाहते हैं, जिनमें शामिल हैं:

- ▶ अंकेंक्षण प्रक्रियाएं
- ▶ हितधारकों की भागीदारी
- ▶ लेखापरीक्षा रिपोर्ट और अन्य लेखापरीक्षा उत्पाद
- ▶ लेखापरीक्षा रिपोर्ट / उत्पादों का संचार और अनुवर्ती कार्रवाई
- ▶ लेखांकन प्रक्रियाएं और वित्तीय रिपोर्टिंग
- ▶ हकदारी प्रक्रियाएं और दावों का निपटान
- ▶ आईटी संचालित और आईटी आधारित पहल
- ▶ मानव संसाधन और क्षमता निर्माण
- ▶ प्रशासनिक दक्षता
- ▶ शिकायत निवारण तंत्र
- ▶ कर्मचारी कल्याण
- ▶ कोई अन्य क्षेत्र जो भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के समग्र मिशन की उपलब्धि में योगदान देता है

योजना की शुरुआत के पहले वर्ष में उत्साहजनक प्रतिक्रिया देखी गई, जिसमें भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय के विंग्स से कुल 59 पात्र आवेदन प्राप्त हुए। सीएजी को वर्ष 2021 के पुरस्कारों के विजेता के रूप में आठ टीमों की घोषणा करते हुए प्रसन्नता है। पुरस्कार प्रदान की गई प्रविष्टियों का चयन एक सतर्क प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है, जिसमें एक विशेषज्ञ समिति द्वारा कठोर संवीक्षा और प्रविष्टियों को शॉर्टलिस्ट किया गया और उसके बाद एक सशक्त समिति द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए प्रस्तावों का स्वतंत्र मूल्यांकन किया गया है। परियोजना के शीर्षक के वर्णानुक्रम में व्यवस्थित, विजेता प्रविष्टियों का विवरण इस प्रकार है।



About CAG's awards for Innovation and Excellence in Public Auditing and Accounting, 2021

The Comptroller and Auditor General of India instituted the scheme for 'CAG's Awards for Innovation and Excellence in Public Auditing and Accounting', to recognize and reward the extraordinary and innovative work done by the officers and staff of the Indian Audit and Accounts Department in the areas of public auditing, accounting, entitlement and support functions. These awards seek to promote innovation and excellence backed by demonstrated exceptional performance and initiatives taken in the field of functional areas, working environment and welfare including:

- ▶ Auditing processes
- ▶ Stakeholder engagement
- ▶ Audit Reports and other audit products
- ▶ Communication and follow up of Audit Reports/products
- ▶ Accounting processes and financial reporting
- ▶ Entitlement processes and settlement of claims
- ▶ IT driven and IT led initiatives
- ▶ Human Resources and Capacity Building
- ▶ Administrative efficiency
- ▶ Grievance Redressal Mechanism
- ▶ Staff Welfare
- ▶ Any other area that contributes to achievement of the overall mission of IA&AD

The first year of introduction of the scheme witnessed an encouraging response, with a total of 59 eligible applications received from various field offices of the IA&AD and wings in the office of the CAG of India.

The CAG is pleased to declare eight teams as the winners of the Awards for the year 2021. The awarded entries have been selected through a meticulous process involving rigorous scrutiny and short listing of the entries by an Expert Committee, followed by independent assessment of the shortlisted proposals by an Empowered Committee. The details of the winning entries, arranged in alphabetical order of the title of the project, are as follows.



उत्पाद शुल्क के अपवंचन को जाँचने के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा में प्रति-सत्यापन

पुरस्कृत कार्यालय - कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उत्तर प्रदेश

उत्कृष्टता का क्षेत्र: अंकक्षण प्रक्रियाएं

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उत्तर प्रदेश ने वेव डिस्टिलरी एंड ब्रेवरीज लिमिटेड, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश द्वारा राज्य आबकारी विभाग में दाखिल किये गए वैधानिक रिटर्न को कर निर्धारिती द्वारा आयकर विभाग में दायर वैधानिक रिटर्न से प्रति-सत्यापन के माध्यम से ₹1,646.04 करोड़ के उत्पाद शुल्क के अपवंचन का पता लगाया।

वेव डिस्टिलरी एंड ब्रेवरीज लिमिटेड, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश एक आबकारी इकाई है जो शराब और अन्य मादक पदार्थों का उत्पादन करती है, जिसके लिए यह शीरा, अनाज और माल्ट जैसे इनपुट और स्पिरिट और वाश जैसे मध्यवर्ती वस्तुओं का उपयोग करती है। लेखापरीक्षा कार्यालय ने कर निर्धारिती द्वारा आयकर अधिकारियों और राज्य आबकारी विभाग को 2013-14 से 2016-17 की अवधि के लिए रिपोर्ट किए गए इनपुट और मध्यवर्ती वस्तुओं की खपत के विवरणों की दुत्तरफी पड़ताल की। यह जांच कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय), लखनऊ, जो स्थानीय आयकर अधिकारियों सहित राज्य में केंद्र सरकार के संगठनों की लेखापरीक्षा करता है, के साथ सूचना साझा करके की गई थी।

प्रति-सत्यापन से पता चला कि कर निर्धारिती ने राज्य आबकारी विभाग को इनपुट और मध्यवर्ती वस्तुओं की कम खपत की सूचना दी थी और इस तरह लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान ₹1,646.04 करोड़ के उत्पाद शुल्क और ब्याज का अपवंचन हुआ।

इस लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, राज्य सरकार ने सभी उप आबकारी आयुक्तों को पिछले 10 वर्षों में दायर वैधानिक रिटर्न के माध्यम से आयकर विभाग को प्रस्तुत अभिलेखों के साथ, आसवनी के अभिलेखों में दर्शाए गए कच्चे माल की खपत के आंकड़ों का मिलान करने का निर्देश दिया। अभिलेखों में पाए गए अंतर, यदि कोई हों, को राजस्व की वसूली के मामले पर विचार करने हेतु ध्यान में लाया जाना है।

यह पहल, एक समान लेखापरीक्षा मुद्दे को उजागर करने में सहयोगी लेखापरीक्षा कार्यालयों के बीच सहकारिता का एक उदाहरण स्थापित करने के अलावा, वास्तविक रिटर्न दाखिल करने और उसके अनुरूप कर संग्रह सुनिश्चित करने में कर निर्धारितियों के बीच अधिक अनुशासन को प्रोत्साहित करके राजस्व अर्जित करने वाले विभागों को लाभान्वित करेगी।

टीम

1. श्री जयंत सिन्हा, आईएएस
2. श्री राज कुमार, आईएएस
3. श्री सुधीर कुमार शुक्ला, व. लेखापरीक्षा अधिकारी
4. श्री गोवर्धन लाल, स. लेखापरीक्षा अधिकारी
5. श्री बी के सिंह, पर्यवेक्षक



Cross verification in Compliance Audit to check evasion of excise duty

Awarded office: Office of the Principal Accountant General (Audit-II), Uttar Pradesh

Area of excellence: Auditing processes

The Office of the Principal Accountant General (Audit-II), Uttar Pradesh detected evasion of excise duty of ₹1,646.04 crore by Wave Distillery and Breweries Ltd., Aligarh, Uttar Pradesh through cross-verification of the statutory returns filed by the assessee in the State Excise Department with those filed in the Income Tax Department.

Wave Distillery and Breweries Ltd., Aligarh, Uttar Pradesh is an excise unit that produces liquor and other intoxicants, for which it uses inputs such as molasses, grain and malt; and intermediaries such as spirit and wash. The audit office cross-checked particulars of consumption of inputs and intermediaries reported by the assessee for the period from 2013-14 to 2016-17 to the Income Tax Authorities and the State Excise Department. This was done by sharing information with the Office of the Director General of Audit (Central), Lucknow, which conducts audit of Central Government organisations in the State including the local Income Tax authorities.

The cross verification revealed that the assessee had under-reported consumption of inputs and intermediaries to the State Excise Department and thereby evaded excise duty and interest thereon of ₹1,646.04 crore during the period of audit.

As a result of this audit, the State Government directed all the Deputy Excise Commissioners to reconcile the figures of consumption of raw materials depicted in the records of the distilleries, with the records submitted to the Income Tax Department through statutory returns filed in the last 10 years. Differences if any, noticed in the records are to be brought to notice for considering the case for recovery of revenue.

This initiative, besides setting forth an example of collaboration among sister audit offices in highlighting a common audit issue, will benefit revenue earning departments by encouraging greater discipline amongst assessee in filing of truthful returns and ensuring commensurate tax collection.

The Team

1. Shri Jayant Sinha, IA&AS
2. Shri Raj Kumar, IA&AS
3. Shri Sudhir Kumar Shukla, Sr. Audit Officer
4. Shri Goverdhan Lal, Asst. Audit Officer
5. Shri B K Singh, Supervisor



राज्य वित्त लेखापरीक्षा रिपोर्ट में ऋण स्थिरता विश्लेषण

पुरस्कृत कार्यालय - कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1), महाराष्ट्र

उत्कृष्टता का क्षेत्र: अंकक्षण प्रक्रियाएं

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1), महाराष्ट्र ने पहली बार एक आर्थिक मॉडल का उपयोग करके राज्य सरकार की ऋण स्थिरता का विश्लेषण करने का प्रयास किया।

राज्य वित्त लेखापरीक्षा रिपोर्ट राज्य के वित्त के लेखापरीक्षित आंकड़ों का भंडार है, जिसमें राज्य की वित्तीय स्थिति का आकलन शामिल है और जो राज्य द्वारा किए गए व्यय और उधार की प्रवृत्तियों के बारे में एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। राज्य के कर्ज की मात्रा और इसकी स्थिरता, विश्लेषण का एक प्रमुख तत्व है। पिछले वर्षों में, राज्य वित्त लेखापरीक्षा रिपोर्टों में तरलता संकेतकों जैसे कि ब्याज/राजस्व प्राप्तियां और ऋण योग्यता संकेतकों जैसे ऋण चुकौती, ऋण प्राप्तियां और निवल ऋण का उपयोग करते हुए राज्य सरकारों की ऋण स्थिरता को इंगित किया जाता था। इस दृष्टिकोण से राज्य में प्रचलित व्यापक आर्थिक स्थितियों को देखते हुए, सार्वजनिक ऋण की स्थिरता और राज्य के लिए उपलब्ध राजकोषीय स्थान के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान नहीं की जा सकती थी।

लेखापरीक्षा कार्यालय ने राज्य की ऋण स्थिरता का विश्लेषण करने के लिए पहली बार डोमर मॉडल का उपयोग किया। डोमर मॉडल के अनुसार यदि वास्तविक आर्थिक विकास दर वास्तविक ब्याज दर से अधिक है, तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सार्वजनिक ऋण एक स्थिर मूल्य में एकाग्र हो जाएगा। यह मॉडल समय की अवधि में वास्तविक विकास दर, वास्तविक ब्याज दर और प्राथमिक शेष के संकेतकों का उपयोग करके राज्य की ऋण चुकौती क्षमता को उसकी व्यापक आर्थिक स्थिति से जोड़ता है।

विश्लेषण के आधार पर लेखापरीक्षा कार्यालय ने टिप्पणी की, कि जबकि राज्य का सार्वजनिक ऋण एक स्थिर स्तर पर अभिसरण कर सकता है, जिससे सार्वजनिक बचत हो सके, डोमर गैप (वास्तविक विकास दर और वास्तविक ब्याज दर के बीच का अंतर) एक स्थिर या लगातार बढ़ती प्रवृत्ति दर्ज नहीं कर रहा था। इस तरह की अंतर्दृष्टि से राज्य सरकार को अपने कर्ज के बेहतर प्रबंधन और मजबूत राजकोषीय नीतियां बनाने में मदद मिलेगी।

टीम

1. श्री सौरभ कुमार जयपुरियार, आईएएस
2. श्री करण वोहरा, आईएएस
3. सुश्री बीनू मैथ्यूस, व. लेखापरीक्षा अधिकारी
4. श्री उन्नीकृष्णन नम्बिसन, स. लेखापरीक्षा अधिकारी

लेखापरीक्षा कार्यालय
Dedicated to Truth in Public Interest

Debt Sustainability Analysis in State Finances Audit Report

Awarded office: Office of the Principal Accountant General (Audit – I), Maharashtra

Area of excellence: Auditing processes

The Office of the Principal Accountant General (Audit-I), Maharashtra attempted an analysis of the debt sustainability of the State Government by using an economic model for the first time.

The State Finances Audit Report is the repository of audited data of State Finances, which includes an assessment of the State's fiscal position and provides an insight into the trends of expenditure and borrowings made by the State. The quantum of debt of the State and its sustainability is a key element of the analysis. In the previous years, the State Finances Audit Reports indicated the debt sustainability of State Governments by using liquidity indicators such as interest/revenue receipts and credit worthiness indicators such as debt repayment, debt receipts and net debt. This approach did not provide insights into the stability of public debt and the fiscal space available to the State, given the prevailing macroeconomic conditions in the State.

The audit office used the Domar Model for the first time to analyse the debt sustainability of the State. The Domar Model states that if the real economic growth rate is greater than the real interest rate, the public debt as a percentage of the Gross State Domestic Product will converge to a stable value. The model links the debt repayment ability of the State to its macroeconomic condition, using the indicators of real growth rate, real interest rate and primary balance over a period of time.

Based on the analysis, the audit office commented that while the public debt of the State should converge to a stable level leading to public savings, the Domar gap (difference between the Real Growth rate and the Real Interest rate) had not been registering a stable or steadily rising trend. Such an insight will help the State Government in better management of their debt and in framing sound fiscal policies.

The Team

1. Shri Saurav Kumar Jaipuriyar, IA&AS
2. Shri Karan Vohra, IA&AS
3. Ms. Binu Matthews, Sr. Audit Officer
4. Shri Unnikrishnan Nambisan, Asst. Audit Officer



इंटरएक्टिव डिजिटल लेखापरीक्षा रिपोर्ट

पुरस्कृत कार्यालय-भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय में सीमा शुल्क लेखापरीक्षा विंग

उत्कृष्टता का क्षेत्र: लेखापरीक्षा रिपोर्ट और अन्य लेखापरीक्षा उत्पाद, हितधारकों की भागीदारी, आईटी संचालित और आईटी आधारित पहल

मुख्यालय में सीमा शुल्क लेखापरीक्षा विंग ने, राजस्व के डिजिटल लेखापरीक्षा उत्कृष्टता केंद्र, बेंगलुरु (सीडार) के साथ 'अन्तर्वर्द्धनीय कंटेनर डिपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशन की कार्यप्रणाली' की निष्पादन लेखापरीक्षा पर पहली इंटरएक्टिव डिजिटल लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार की, जिसे संसद के दोनों सदनों में जनवरी 2019 में प्रस्तुत किया गया था।

इंटरएक्टिव डिजिटल लेखापरीक्षा रिपोर्ट की संकल्पना सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों को उपयोगकर्ता के अनुकूल, इंटरैक्टिव और खोज कार्यों के संदर्भ में अधिक बहुमुखी बनाने की दृष्टि से की गई थी। सीमा शुल्क लेखापरीक्षा विंग ने प्रोफेशनल प्रैक्टिसेज ग्रुप के सहयोग से नीतिगत मामलों को सुलझाया, जिसमें रिपोर्ट तैयार करने के लिए संस्थागत व्यवस्था का निर्माण, हितधारक परामर्श, कानूनी जांच और अनुपालन मूल्यांकन शामिल हैं। सीडार ने एक उपयुक्त एजेंसी की नियुक्ति करने और संबंधित तकनीकी पहलू जिसमें प्रौद्योगिकी समाधान की अवधारणा, पहचान और कार्यान्वयन शामिल हैं, पर कार्य किया।

इंटरएक्टिव डिजिटल लेखापरीक्षा रिपोर्ट को एक ऑनलाइन वेब संस्करण और एक पीडीएफ संस्करण के रूप में अंतर्निहित इंटरैक्टिव डेटा विजुअलाइजेशन सुविधाओं के साथ तैयार किया गया था। रिपोर्ट एक गहन खोज सुविधा प्रदान करती है, जिससे एक अंकेक्षित इकाई रिपोर्ट में दर्शाये गये मुद्दों की अपनी संबंधित सूची को आसानी से पुनः प्राप्त कर सकती है।

रिपोर्ट को प्रस्तुत करने पर, संसद के दोनों सदनों, वित्त मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय और कानून और न्याय मंत्रालय के साथ व्यापक परामर्श शामिल था। लेखापरीक्षा रिपोर्ट की गोपनीयता, गैर-प्रकटीकरण खंड के साथ सेवा स्तर समझौते में प्रवेश करके और रिपोर्ट के विकास पर काम कर रहे अधिकृत उपयोगकर्ताओं को लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ एक अलग सर्वर आवंटित करके सुनिश्चित की गई थी। रिपोर्ट को आईटी अधिनियम, 2000 में निर्दिष्ट तरीके से डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करके प्रमाणित किया गया है।

इस रिपोर्ट को हितधारकों द्वारा व्यापक रूप से सराहा गया था। यूरोपीय सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट ऑर्गनाइजेशन ने इस पहल की सराहना की और इसे सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट समुदाय के उत्कृष्ट कार्य प्रणाली के अंतर्गत सूचीबद्ध किया।

टीम

1. सुश्री शैफाली अंडलीब, आईएएस
2. श्री दीपक मैथ्युस, आईएएस
3. श्री एन एन सुब्रमणियन, आईएएस
4. श्री रजनीश शर्मा, व.लेखापरीक्षा अधिकारी
5. श्री सौमंद्र सरन, व.लेखापरीक्षा अधिकारी
6. सुश्री एम मरगथवल्ली, व.लेखापरीक्षा अधिकारी
7. श्री एम के लेइंगकलेमबा, स. लेखापरीक्षा अधिकारी



Interactive Digital Audit Report

Awarded office: Customs Audit Wing at Office of the CAG of India

Areas of excellence: Audit reports and other Audit products, Stakeholder engagement, IT driven and IT led initiatives

Customs Audit Wing at Headquarters, along with the Centre of Excellence in Digital Audit of Revenue, Bengaluru (CEDAR) developed the first Interactive Digital Audit Report on 'Performance Audit of Working of Inland Container Depots and Container Freight Stations', which was tabled in both Houses of Parliament in January 2019.

The Interactive Digital Audit Report was conceived with a view to making CAG's Audit Reports more user-friendly, interactive and versatile in terms of search functions. Customs Audit Wing, in collaboration with Professional Practices Group, addressed the policy matters comprising creation of institutional arrangement for bringing out the report, stakeholder consultation, legal scrutiny and compliance evaluation. CEDAR undertook the work of engaging a suitable agency and the related technological aspect involving conceptualisation, identification and implementation of the technology solution.

The Interactive Digital Audit Report was developed both as an online web version and a pdf version with embedded interactive data visualisation features. The report provides a deep search facility, whereby an audited entity can readily retrieve their respective list of issues that have been featured in the report.

Laying of the report involved extensive consultation with both Houses of Parliament, Ministry of Finance, Ministry of Parliamentary Affairs and Ministry of Law and Justice. Confidentiality of the Audit Report was ensured by entering into Service Level Agreement with non-disclosure clause and by allotting a separate server with login credentials to authorised users working on development of the report. The report has been authenticated using digital signatures in the manner prescribed in the IT Act, 2000.

The report was widely acclaimed by stakeholders. The European Organisation of Supreme Audit Institutions commended this initiative and listed it under the Good Practices of the Supreme Audit Institutions community.

The Team

1. Ms. Shefali Andaleeb, IA&AS
2. Shri Deepak Mathews, IA&AS
3. Shri N N Subramanian, IA&AS
4. Shri Rajneesh Sharma, Sr. Audit Officer
5. Shri Soumendra Saran, Sr. Audit Officer
6. Ms. M Maragathavalli, Sr. Audit Officer
7. Shri M K Leingaklemba, Asst. Audit Officer



पेंशन संशोधन मामलों के आईटी सक्षम निपटान

पुरस्कृत कार्यालय - कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा

उत्कृष्टता का क्षेत्र: हकदारी प्रक्रियाएं और दावों का निपटान,
आईटी संचालित और आईटी आधारित पहल

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा ने लगभग 1.75 लाख पेंशन मामलों, जिनमें 7 वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार संशोधन की आवश्यकता थी, के प्रबंधन और समीक्षा के लिए एक ऑनलाइन डायरी प्रबंधन प्रणाली का डिजाइन और संचालन किया।

इससे पहले, पेंशन मामलों का संशोधन मैन्युअल रूप से किया जाता था, जो फाइलों की वास्तविक आदान-प्रदान के कारण बोज़िल था। कागजों की भारी मात्रा के कारण प्रत्याशित समस्याओं को दूर करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि काम समय पर पूरा किया जाए, लेखा एवं हकदारी कार्यालय ने पेंशन मामलों की प्राप्ति से लेकर पेंशन भुगतान आदेशों के प्राधिकरण तक पूरी प्रक्रिया को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए एप्लिकेशन विकसित किया। ऑनलाइन डायरी प्रबंधन प्रणाली राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, हरियाणा की मदद से विकसित की गई थी और दिसंबर 2018 में शुरू की गई थी।

यह वेब आधारित एप्लिकेशन एक सार्वजनिक डोमेन पर होस्ट किया गया है और इसे आहरण और संवितरण अधिकारी, कोषाधिकारी और पेंशनभोगी द्वारा आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। एक डैशबोर्ड पेंशन मामलों की स्थिति प्रदान करता है, जिसमें मामलों की उपलब्धता, लेखा एवं हकदारी कार्यालय द्वारा अधिकृत मामलों की सूची के साथ-साथ कारण सहित अस्वीकृत या लौटाए गए मामलों की सूची भी शामिल है। पेंशनभोगी को एसएमएस संदेश के माध्यम से संशोधित पेंशन भुगतान आदेश डाउनलोड करने के लिए लिंक प्राप्त होता है।

एप्लिकेशन के कार्यान्वयन ने डेटा सत्यापन की आसान सुविधा प्रदान की है, दस्तावेजों के गुम होने की संभावना को समाप्त कर दिया है, डाक देरी और डाक लागत से छुटकारा दिलाया है और औसत प्रसंस्करण समय को 28 दिनों से घटाकर 5 दिन कर दिया है।

टीम

1. श्री विशाल बंसल, आईएएस
2. सुश्री धनलक्ष्मी चौरसिया, आईएएस
3. श्री सुमीत कुमार, आईएएस
4. श्री विजय गर्ग, व.लेखा अधिकारी
5. श्री पवन कुमार, व. लेखापाल



IT enabled settlement of pension revision cases

Awarded office: Office of the Accountant General (Accounts & Entitlement), Haryana

Areas of excellence: Entitlement processes & settlement of claims,
IT driven and IT led initiatives

The Office of the Accountant General (Accounts & Entitlement), Haryana designed and operationalised an Online Diary Management System to manage and review the approximately 1.75 lakh pension cases that needed revision in accordance with the recommendations made by the 7th Central Pay Commission.

Prior to this, the revision of pension cases was done manually, which was cumbersome owing to the physical movement of files. In order to overcome the problems anticipated due to the huge volume of papers and ensure that the work was completed in a timely manner, the A&E office developed the application to computerise the entire process right from receipt of pension cases to authorisation of the pension payment orders. The Online Diary Management System was developed with the help of National Informatics Centre, Haryana and was rolled out in December 2018.

This web based application is hosted on a public domain and can be easily accessed by the Drawing and Disbursing officer, the Treasury officer and the pensioner. A dashboard provides the status of the pension cases including availability of cases, list of cases authorised by the A&E office as well as those rejected or returned, along with the reasons thereof. The pensioner receives the link to download the revised pension payment order via SMS message.

Implementation of the application has facilitated easier data validation, eliminated chances of misplacement of documents, got rid of postal delays and postal costs and reduced the average processing time from 28 days to 5 days.

The Team

1. Shri Vishal Bansal, IA&AS
2. Ms. Dhanlaxmi Chourasia, IA&AS
3. Shri Sumeet Kumar, IA&AS
4. Shri Vijay Garg, Asst. Accounts Officer
5. Shri Pawan Kumar, Sr. Accountant



अस्पताल प्रबंधन की निष्पादन लेखापरीक्षा

पुरस्कृत कार्यालय - कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1), उत्तर प्रदेश

उत्कृष्टता का क्षेत्र: अंकक्षण प्रक्रियाएं, लेखापरीक्षा रिपोर्ट और अन्य लेखापरीक्षा उत्पाद, हितधारकों की भागीदारी

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1), उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश में अस्पताल प्रबंधन के परिणाम आधारित निष्पादन लेखापरीक्षा का एक सफल प्रायोगिक परीक्षण किया।

अब तक, स्वास्थ्य क्षेत्र की लेखापरीक्षाओं में अनुपालन मुद्दों, इनपुट और आउटपुट के बेमेल, गुणवत्ता आश्वासन तंत्र की दक्षता आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया था। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में आम आदमी के विश्वास को मजबूत करने पर भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के फोकस को ध्यान में रखते हुए, प्राप्त हुई देखभाल और सरकारी अस्पतालों से अपेक्षित देखभाल की गुणवत्ता के बीच अंतर की पहचान करने और उन्हें सुधारात्मक कार्रवाई के लिए हितधारकों के ध्यान में लाने का निर्णय लिया गया था।

परिणाम आधारित लेखापरीक्षा राज्य में प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य देखभाल स्तरों पर प्राप्त रोगी देखभाल पर केंद्रित थी। अस्पताल प्रणाली में बाह्य रोगी और भर्ती रोगी सेवाएं, मातृत्व सेवाएं, आपातकालीन सेवाएं, नैदानिक सेवाएं, संक्रमण नियंत्रण और दवा प्रबंधन जैसी सभी कार्यकलाप शामिल हैं, इनका मूल्यांकन चयनित जिला-स्तर के अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पूर्व-निर्धारित परिणाम संकेतकों/मानदंडों पर किया गया था।

लेखापरीक्षा नमूना अस्पतालों की सापेक्ष ताकत और कमजोरियों को उजागर करने में सक्षम थी, जिससे बेहतर अस्पताल प्रबंधन के लिए लक्षित हस्तक्षेप का मामला बना। लेखापरीक्षा में यह भी सामने आया कि सरकार को स्वास्थ्य परिणामों में बदलाव की सुविधा के लिए, रोगी देखभाल हेतु एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने, रोगी प्राथमिकताओं के अनुरूप संसाधन आवंटित करने और जिला अस्पतालों की निगरानी और कामकाज में सुधार करने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रत्युत्तर में, उत्तर प्रदेश सरकार ने संक्रमण नियंत्रण दिशानिर्देश, रेफरल दिशानिर्देश और रोगाणुरोधी दिशानिर्देश जारी किये और लेखापरीक्षा अनुशंसाओं पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस अग्रणी लेखापरीक्षा के बाद छह अन्य राज्यों में इसी तरह की लेखापरीक्षा की गई।

टीम

1. श्री सरित जफ़ा, आईएएस
2. श्री संदीप डाबर, आईएएस
3. श्री दीपक कुमार श्रीवास्तव, व.लेखापरीक्षा अधिकारी
4. श्री राम कुमार, व.लेखापरीक्षा अधिकारी
5. श्री वी बी सिंह, व.लेखापरीक्षा अधिकारी
6. श्री गणेश चंद्र झा, व.लेखापरीक्षा अधिकारी
7. स्वर्गीय श्री शेषाद्रि शंकर पांडे, स. लेखापरीक्षा अधिकारी
8. श्री सजल कुमार घोष, स. लेखापरीक्षा अधिकारी



Performance Audit of Hospital Management

Awarded office: Office of the Principal Accountant General (Audit - I), Uttar Pradesh

Areas of excellence: Auditing processes, Audit reports and other Audit products, Stakeholder engagement

The Office of the Principal Accountant General (Audit-I), Uttar Pradesh, carried out a successful pilot of the outcomes based performance audit of Hospital Management in Uttar Pradesh.

Hitherto, audits on health sector had focused on compliance issues, mismatch of inputs and outputs, efficiency of quality assurance mechanism, etc. In view of the focus of India's National Health Policy 2017 on strengthening the trust of the common man in the public healthcare system, it was decided to identify the gaps between the quality of care received and that expected from Government hospitals and bring these to the notice of the stakeholders for corrective action.

The outcomes based audit focused on patient care received at the primary and secondary health care levels in the State. All activities in the hospital system including out-patient and in-patient services, maternity services, emergency services, diagnostic services, infection control and drug management were assessed on pre-determined outcome indicators/criteria in the sampled district-level hospitals and community health centres.

Audit was able to highlight the relative strengths and weaknesses of the sampled hospitals, thereby making a case for targeted interventions for better hospital management. The audit also brought out that the Government needed to adopt an integrated approach to patient care, allocate resources consistent to patient priorities, and improve the monitoring and functioning of district hospitals towards facilitating change in health outcomes.

In response to the Audit Report, the Government of Uttar Pradesh introduced Infection Control Guidelines, Referral Guidelines and Anti-microbial Guidelines and assured action on the audit recommendations. This pioneering audit was followed by similar audits in six other States.

The Team

1. Shri Sarit Jafa, IA&AS
2. Shri Sandeep Dabur, IA&AS
3. Shri Deepak Kumar Srivastava, Sr. Audit Officer
4. Shri Ram Kumar, Sr. Audit Officer
5. Shri V.B. Singh, Sr. Audit Officer
6. Shri Ganesh Chandra Jha, Sr. Audit Officer
7. Late Shri Sheshadri Shankar Pandey, Asst. Audit Officer
8. Shri Sajal Kumar Ghosh, Asst. Audit Officer



स्टॉर्म वाटर प्रबंधन की निष्पादन लेखापरीक्षा

पुरस्कृत कार्यालय - कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), कर्नाटक

उत्कृष्टता का क्षेत्र: अंकेक्षण प्रक्रियाएं, लेखापरीक्षा रिपोर्ट और अन्य लेखापरीक्षा उत्पाद, हितधारकों की भागीदारी

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), कर्नाटक ने बेंगलुरु में नमूना क्षेत्रों में स्टॉर्म वाटर निकासी बुनियादी ढांचे का विश्लेषण करने और जल निकासी संरचनाओं, जल निकायों, अतिक्रमणों, भूमि उपयोग पैटर्न पक्का क्षेत्र/खुले क्षेत्रों में परिवर्तन/हरित आवरण में परिवर्तन, आदि की पहचान करने के लिए सेटेलाईट इमेजरी को एक अभिनव साक्ष्य एकत्रण तकनीक के रूप में उपयोग किया।

बेंगलुरु शहर की आबादी में भारी वृद्धि के परिणामस्वरूप, गंभीर परिणामों के साथ तेजी से शहरीकरण हुआ है, जिसमें विकट बढ़ती बढ़ती आवृत्ति और घरेलू खपत के लिए पानी की तीव्र कमी शामिल है। लेखापरीक्षा कार्यालय ने यह पता लगाने के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा की कि क्या बेहतर स्टॉर्म वाटर प्रबंधन शहरी बाढ़ और पानी की कमी की समस्याओं से एक साथ निपट सकता है। इसके लिए एक समयावधि में स्टॉर्म वाटर के बुनियादी ढांचे के नक्शे के विश्लेषण की आवश्यकता थी।

विभिन्न प्राधिकरणों के पास पूर्ण मानचित्रों की कमी और लेखापरीक्षा साक्ष्य उपलब्ध कराने के प्रतिरोध की चुनौतियों का सामना करते हुए, लेखापरीक्षा कार्यालय ने साक्ष्य एकत्र करने के लिए सेटेलाईट इमेजरी को एक उपयुक्त विकल्प के रूप में पहचान की। कार्यालय ने क्षेत्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, बेंगलुरु के साथ तकनीकी सहायता के लिए सहयोग लिया, जिसमें उपग्रह इमेजरी तक पहुंच के साथ-साथ भू-स्थानिक छवि विश्लेषण में लेखापरीक्षा कर्मियों को प्रशिक्षण भी शामिल था। लेखापरीक्षा टीम ने भूमि उपयोग और भूमि आवरण में परिवर्तन की पहचान और मात्रा निर्धारित करने के लिए लगभग 50 वर्षों की अलग-अलग समय अवधि से उपग्रह छवियों को सुपरइम्पोज किया। टीम ने संभावित उल्लंघन दिखाने वाले स्थानों का दौरा किया और वीडियो बनाए, जिन्हें बाद में क्यूआर कोड और यू ट्यूब लिंक के रूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया गया था।

इस विशिष्ट लेखापरीक्षा पद्धति के परिणामस्वरूप, ठोस सबूत से समर्थित उच्च गुणवत्ता वाली विविध लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ प्राप्त हुईं। अंकेक्षित इकाई ने बंगलौर विकास प्राधिकरण और शहर के नगर निगम के बीच डेटाबेस का मिलान करने, वार्षिक ठेके पर स्टॉर्म वाटर नालों के रखरखाव का कार्य सौंपने और 'एज बिल्ट ड्राईंग्स' और 'पूर्णता योजना' और उनके संरक्षण पर जोर देना जैसी कार्रवाइयां शुरू की हैं।

टीम

1. सुश्री ई पी निवेदिता, आईएएस
2. सुश्री ऐ जे अमिता, आईएएस
3. श्री के एल बालकृष्ण, व.लेखापरीक्षा अधिकारी
4. श्री यू रविकुमार, व.लेखापरीक्षा अधिकारी
5. श्री पी मोहन हर्ले, पर्यवेक्षक
6. श्री राय अभिलाष, लेखापरीक्षक



Performance Audit of Management of Storm Water

Awarded office: Office of the Principal Accountant General (Audit – I), Karnataka

Areas of excellence: Auditing processes, Audit Reports & other Audit products, Stakeholder engagement

The Office of the Principal Accountant General (Audit-I), Karnataka used satellite imagery as an innovative evidence gathering technique to analyse the storm water drainage infrastructure in sampled areas in Bengaluru and identify changes in drainage structures, water bodies, encroachments, land use patterns, paved area/changes in open areas/green cover, etc.

Mammoth increase in the population of Bengaluru city has resulted in rapid urbanisation with serious consequences, including increased frequency of severe flooding and acute scarcity of water for domestic consumption. The audit office took up the performance audit to find whether better storm water management could simultaneously tackle the problems of urban flooding and water scarcity. This needed analysis of storm water infrastructure maps over a period of time.

Faced with the challenges of lack of complete maps with various authorities and resistance to providing audit evidence, the audit office identified satellite imagery as a suitable alternative for collecting evidence. The office collaborated with Regional Remote Sensing Centre, Indian Space Research Organisation, Bengaluru for technical assistance including access to satellite imagery as well as training the audit personnel in geospatial image analysis. The audit team superimposed satellite images from different time periods spanning about 50 years to identify and quantify changes in land use and land cover. The team conducted field visits to the sites showing potential violations and captured videos, which were then, included in the Audit Report in the form of QR codes and YouTube links.

The unique audit methodology resulted in high quality of diverse audit observations supported by sound evidence. The audited entity has initiated actions such as reconciliation of databases between Bangalore Development Authority and the City's Municipal Corporation; entrusting the maintenance of storm water drains on annual contract; and insisting on 'as built drawings' and 'completions plans' and their preservation.

The Team

1. Ms. E P Nivedita, IA&AS
2. Ms. A J Amitha, IA&AS
3. Shri K L Balakrishna, Sr. Audit Officer
4. Shri U Ravikumar, Sr. Audit Officer
5. Shri P Mohan Herle, Supervisor
6. Shri Rai Abhilash, Auditor



उच्च शिक्षा में परिणाम आधारित लेखापरीक्षा की योजना और संचालन

पुरस्कृत कार्यालय - कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1), राजस्थान

उत्कृष्टता का क्षेत्र: अंकक्षण प्रक्रियाएं, हितधारकों की भागीदारी

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1) राजस्थान ने उच्च शिक्षा के परिणामों की अपनी तरह की पहली लेखापरीक्षा आयोजित करने में नौ लेखापरीक्षा कार्यालयों का नेतृत्व किया।

उच्च शिक्षा की पारंपरिक लेखापरीक्षा में वे अंकक्षण प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जो मुख्य रूप से इनपुट जैसे कि योजनाओं और नीतियों का अस्तित्व, संसाधनों का उपयोग आदि और ठोस आउटपुट जैसे उच्च शिक्षा संस्थानों की पर्याप्त संख्या, भौतिक बुनियादी ढांचे का अस्तित्व आदि पर केंद्रित होती हैं। हालांकि, हाल के समय में, रोजगार योग्यता, अनुसंधान परियोजनाओं के माध्यम से समाज में योगदान, शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता में समानता जैसे 'परिणामों' की अवधारणा को प्रमुखता मिली है। इसलिए, उच्च शिक्षा क्षेत्र में परिणामों की उपलब्धि के आंकलन की दिशा में अनुपालन और औचित्य केंद्रित लेखापरीक्षा के पारंपरिक दृष्टिकोण से परे लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को विकसित करना आवश्यक समझा गया।

मुख्य हितधारकों—छात्र, समाज और सरकार द्वारा अपेक्षित परिणामों को समझने के लिए, लेखापरीक्षा कार्यालय ने सरकारी निकायों, विशेषज्ञों और शिक्षाविदों के साथ व्यापक रूप से बातचीत की और उनके इनपुट और विश्लेषण के आधार पर, 26 प्रमुख परिणाम संकेतक और संबंधित इनपुट—आउटपुट संकेतक प्राप्त किये। लेखापरीक्षा ने राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा विश्वविद्यालयों को उनकी मान्यता प्रक्रिया में ग्रेड देने के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग प्रणाली के आधार पर मात्रात्मक प्रॉक्सी मानदंड विकसित किए।

इस पहल ने भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग को उच्च शिक्षा क्षेत्र में एक व्यापक 'परिणाम लेखापरीक्षा' पद्धति प्रदान की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में सरकार द्वारा पहचाने गए कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में रिपोर्ट किया गया था। लेखापरीक्षा टिप्पणियों के आधार पर, राज्य सरकार ने एनएएसी मान्यता प्रक्रिया में सहायता के लिए सभी सात डिवीजन में डिवीजन स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन सेल की स्थापना करने, सभी कॉलेज प्राचार्यों को विकलांग व्यक्तियों के विकलांगजन अधिनियम 1995 के अनुसार दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार और एनएएसी नियमावली में विनिर्दिष्ट दिव्यांग अनुकूल सुविधाएं प्रदान करने के निर्देश देने, और सरकारी और निजी कॉलेजों में रोजगारोन्मुखी कौशल विकास पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए 10 संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन का निष्पादन करने जैसे सुधारात्मक उपाय किये।

टीम

1. श्री अक्षय गोपाल, आईएएस
2. श्री सतीश चंद गुप्ता, व.लेखापरीक्षा अधिकारी
3. श्री जेम्स के सी, व.लेखापरीक्षा अधिकारी
4. श्री हेमंत शर्मा, व.लेखापरीक्षा अधिकारी
5. श्री आर एस दुसाद, व.लेखापरीक्षा अधिकारी
6. श्री रविंद्र कुमार जांगिड़, स. लेखापरीक्षा अधिकारी
7. श्री प्रसेनजीत दत्ता, स. लेखापरीक्षा अधिकारी



Planning and conduct of Outcome Based Audit in Higher Education

Awarded office: Office of the Principal Accountant General (Audit – I), Rajasthan

Areas of excellence: Auditing processes, Stakeholder engagement

The Office of the Principal Accountant General (Audit-I) Rajasthan led nine audit offices in conducting the first-of-its-kind audit of Outcomes of Higher Education.

Traditional audits of Higher Education involve audit processes that are primarily focussed on inputs such as existence of plans and policies, utilisation of resources, etc. and tangible outputs such as adequate number of Higher Education Institutions, existence of physical infrastructure, etc. However, in recent times the concept of 'outcomes' such as employability, contribution to society through research projects, equity in access and quality of education, have gained primacy. Therefore, it was considered necessary to evolve audit processes beyond the traditional approach of compliance and propriety focussed audits, towards assessment of achievement of outcomes in the Higher Education sector.

In order to understand the outcomes expected by the main stakeholders-students, society and Government, the audit office interacted extensively with government bodies, experts and educationists; and based on their inputs and analysis, arrived at 26 key outcomes indicators and related input-output indicators. Audit developed quantitative proxy criteria based on the scoring system used by the National Assessment and Accreditation Council (NAAC) for awarding grades to universities in their accreditation process.

This initiative has given the IA&AD a comprehensive 'outcomes audit' methodology in the Higher Education Sector. Many of the thrust areas identified by the Government in the National Education Policy, 2020 were reported on in the Audit Report. Based on the audit observations, the State Government took corrective measures including establishment of Divisional Level Quality Assurance Cells in all seven divisions to aid the NAAC accreditation process, directions to all the College Principals to provide specially-abled friendly facilities as prescribed in Rights of Persons with Disability Act, 1995 and NAAC Manual, and execution of Memorandum of Understanding with 10 institutions for providing job oriented skill development courses in government and private colleges.

The Team

1. Shri Akshay Gopal, IA&AS
2. Shri Satish Chand Gupta, Sr. Audit Officer
3. Shri James K C, Sr. Audit Officer
4. Shri Hemant Sharma, Sr. Audit Officer
5. Shri R S Dusad, Sr. Audit Officer
6. Shri Ravindra Kumar Jangid, Asst. Audit Officer
7. Shri Prasenjit Dutta, Asst. Audit Officer



सिस्टम ऑटोमेशन इनिशियेटिव ट्रेनिंग एप्लिकेशन

पुरस्कृत कार्यालय - भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय में प्रशिक्षण विंग

उत्कृष्टता का क्षेत्र: आईटी संचालित और आईटी आधारित पहल, मानव संसाधन और क्षमता निर्माण, प्रशासनिक दक्षता

मुख्यालय में प्रशिक्षण विंग ने भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में प्रशिक्षण कार्यकलापों से जुड़े प्रशासनिक कार्यकलापों के पूर्ण कार्य प्रवाह को स्वचालित करने के लिए एक पोर्टल विकसित और संचालित किया।

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण अवसंरचना के भौगोलिक प्रसार के कारण, भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग का प्रशिक्षण डेटाबेस पहले या तो प्रशिक्षण संस्थानों में या उपयोगकर्ता कार्यालयों में विकेंद्रीकृत रूप से मौजूद था। प्रशासनिक प्रक्रियाओं, सभी उपयोगकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण सामग्री की उपलब्धता आदि के संबंध में बाधाएं आती थीं। इसके अलावा, प्रशिक्षण आवश्यकताओं को वास्तविक प्रशिक्षण आवश्यकताओं की अपेक्षा प्रशिक्षण की पूर्व-निर्धारित सूचियों द्वारा संचालित किया जा रहा था।

इन बाधाओं को दूर करने के लिए सिस्टम ऑटोमेशन इनिशियेटिव ट्रेनिंग पोर्टल विकसित किया गया है। प्रणाली ने प्रशिक्षण आवश्यकताओं के विश्लेषण से लेकर प्रभाव मूल्यांकन तक, प्रशिक्षण गतिविधियों के संपूर्ण कार्यप्रवाह को स्वचालित कर दिया है, जिससे प्रशासनिक कार्य की दक्षता में सुधार हुआ है। विभाग के प्रत्येक कर्मचारी के पास प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षण कैलेंडर, पाठ्यक्रम कार्यक्रम, प्रशिक्षण सामग्री, केस स्टडी आदि की पहुंच है। इसके अलावा, प्रणाली प्रशिक्षण आवश्यकताओं के मूल्यांकन में कर्मचारियों की भागीदारी को सक्षम बनाती है, साथ ही इच्छुक कर्मचारियों को संकाय भूमिकाएं लेने और किसी विशेष प्रशिक्षण में रुचि व्यक्त करने के अवसर प्रदान करती है।

एप्लिकेशन को ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पूरी तरह से इन-हाउस विकसित किया गया है। सभी मॉड्यूल में निर्मित दो-चरणीय सत्यापन डेटा गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद करता है। हितधारकों को उनके लिए प्रासंगिक सूचना के ई-मेल और एसएमएस के माध्यम से स्वचालित संप्रेषण उन्हें तत्काल सूचना और अलर्ट प्रदान करता है।

यह प्रणाली जनवरी 2020 से काम कर रही है और पोर्टल के माध्यम से इन-हाउस प्रशिक्षण सहित लगभग 1,100 प्रशिक्षण आयोजित किए जा चुके हैं। इस पोर्टल ने विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उपयोगकर्ताओं से समवर्ती कनेक्शनों को सफलतापूर्वक संभाला है।

टीम

1. सुश्री अलका रेहानी भारद्वाज, आईएएएस
2. सुश्री जया भगत, आईएएएस
3. श्री अविनाश निलांकर, आईएएएस
4. सुश्री सौमिनी एस, व.लेखापरीक्षा अधिकारी
5. सुश्री वर्धा टीना, स. लेखापरीक्षा अधिकारी
6. श्री जॉयदीप मुखर्जी, स. लेखापरीक्षा अधिकारी



System Automation Initiative Training Application

Awarded office: Training Wing at Office of the CAG of India

Areas of excellence: IT driven and IT led initiatives, Human Resources and Capacity Building, Administrative efficiency

Training Wing at Headquarters developed and operationalised a portal to automate the complete workflow of administrative activities connected with training activities in the IA&AD.

Due to the geographical spread of the sizeable training infrastructure in IA&AD, the training database of IA&AD earlier existed in a decentralised manner either in the Training Institutes or in the user offices. There were constraints with respect to administrative processes, availability of training material to all users, etc. Besides, training requirements were driven by pre-determined lists of training rather than actual training needs.

The System Automation Initiative Training portal has been developed to address these constraints. The system has automated the complete workflow of the training activities, from training needs analysis to impact assessment, thereby improving the efficiency of administrative function. Every employee of the department has access to training calendars of the Training Institutes, course schedules, training materials, case studies, etc. In addition, the system enables the participation of employees in the training needs assessment, as well as provides opportunities to interested employees to take up faculty roles and express interest in a particular training.

The application has been developed entirely in-house using open source technology. A two-step verification built in all modules helps in ensuring data quality. Automation of communication through e-mail and SMS to the stakeholders, of information relevant to them provides them with instant information and alerts.

The system is in operation since January 2020, and about 1,100 trainings, including in-house trainings, have been organised through the portal. It has successfully handled concurrent connections from a large number of users located in different geographical areas.

The Team

1. Ms. Alka Rehani Bhardwaj, IA&AS
2. Ms. Jaya Bhagat, IA&AS
3. Shri Avinash Nilankar, IA&AS
4. Ms. Sowmini S, Sr. Audit Officer
5. Ms. Vardha Teena, Asst. Audit Officer
6. Shri Joydeep Mukherjee, Asst. Audit Officer





भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
Indian Audit and Accounts Department

पॉकेट-९, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-११० ००२
Pocket-9, Deen Dayal Upadhyaya Marg, New Delhi-110 002